two sites, viz extension of Tarapur and Bhima, and in Goa, one site Lohem, have been studied by the Committee in detail, in addition to some other sites were only preliminary investgationsw ere carried out

(c) The Committee's Report on the Western Region (excluding Goa) has been received As regards Goa, a separate report is under preparation by the Committee The main findings of the Committee, which is an internal body set up to assist Government in its decision making, are under examination

Loading of Coal Wagons at N.C.D.C. Singrauli coal fields

1353 SHRI RANA BAHADUR SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether loading of coal wagons at the N C D.C Singrauli coal fields is done on a contract basis;

(b) whether this practice leads to an inordinate exploitation of workers by contractors who make huge profits;

(c) whether this practice leads to unemployment of loaders upto 20 days a month; and

(d) if so, the steps proposed to remedy the situation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) A part of the loading of coal in the Singrauli coalfield is being done on a contract basis.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir. Loaders are idle only on the few occasions when wagons are not supplied by the Railways.

(d) It is proposed to abolish the contract system in stages.

Over Time Allowance to Security Guards of Gorbi Collieries of N C.D.C.

1354. SHRI RANA BAHADUR SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have taken any decision on the representation of the security guards of the Gorbi Collieries of N.C.D C. in Sengrauli regarding payment of overtime allowance;

(b) if so, the decision taken thereon; and

(c) if not, the time by which the decision is expected to be taken?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD): (a) and (b) Overtime allowance is being paid to the Security Guards at the Borbi Project of National Coal Development Corporation

(c) Does not arise

Supply of Coal by N.C.D.C. Coal Fields to Birla Firm at Renukoot

1355 SHRI RANA BAHADUR SINGH: Will the Minister of ENERGY be pleased to state

(a) whether large scale supply of coal has been made by N.C.D.C. coal fields at Sengrauli to Birla firm at Renukoot where the metering device was out of order;

(b) how was the quantity of coal supplied assessed; and

(c) the steps proposed to be taken to prevent loss to Government in such cases of metering device going out of order?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD). (a)

to (c). Coal from the Singrauli Coalfields is supplied to the Renusagar Power House at Renusagar of Birlas through an aerial ropeway and the quantity is weighted by the Belt Weighing Machine at the Renusagar end In case of break-down of the machine at Renusagar, the quantity of coal supplied is assessed by the total number of buckets supplied. To ensure a double check a weighing machine at the loading end is also being installed.

उत्तर बिहार में उद्योग

1356. **श्री विभूति मिश्र** क्या **उद्योग और नागरित पूर्ति** मंत्री उत्तर बिहार में विकास के बारे में 8 मई 1974 के अनाराकित प्रश्न सख्या 9564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने का कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर बिहार में कोई उद्योग स्थापित करने की इस बीच कोई कोशिश की हैं , और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर बिहार के प्रत्येक जिले में उपयक्त उद्योग स्थापित करने का है ?

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौय) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर बिहार में उद्योगो की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए है .—

पाच जिले यथा , चम्पारन दरभगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा सहरसा औद्योगिक दृष्टि स पिछड़े माने गए है तथा वहा स्थित औद्योगिक परि योजनाओं के लिए राष्ट्रीय वित्त निगमों से रियायती वित्त पाने तथा आयकर में राहत पाने के पात्र समझे गए है ।

तीन जिलों, यथा चम्पारन, दरभगा तथा सहरसा का चयन पिछड़े हुए जिलो के रूप में किया गया है जो 1974–75 में अचल निवेश पर सीधी केन्द्रीय राज सहायता मंजूर की जाने तथा वर्ष 1974–75 में लघु उद्योगों के लिए विशेष आयात की सुविधाए दिए जाने के लिए अर्ह समझे गए हैं। इन पिछडे जिलो के लिए 1067257 रु० की कुल सहायता राशि मजूर और वितरित की गई है ।

मुजफ्फरपुर नगर स्थित विस्तार केन्द्र के साथ साथ लघु उद्योग सेवा सस्थान, पटना लघु उद्योगों के विकास का बढ़ावा देने के लिए वृहत परामर्शदायी तथा अन्य विस्तार सेवाये उपलब्ध कराता है । इन सेवाओं में औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण, सघन प्रभियान, सगोष्ठिया, एन० एस० आई० सा० में खरीदने के लिए मशीनों की सख्या को सिफारिश करने, बैंकों आदि से वित्तीय सहायता लेने में सहायता करना सम्मिलित है ।

लघु उद्योग सेवा सस्थान, पटना, द्वारा सहरसा, मारन, दरभगा मुजफ्फरपुर, चम्पारन और पूर्णिया का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था , इसके अलावा पता चला है कि प्रमुख बैंको ने सभी जिलों की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की है ।

लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा सहरसा में एक गहन औद्योगिक विकास कार्यक्रम बनाया गया है ।

केन्द्र द्वारा प्रचारित ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तगत राज्य सरकार को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । पहली बार में बिहार को दी गई पाच